जानना चाहता हूं कि इस प्रश्नोत्तर का संबंध सीमा की सड़कों से है तो डिफेंस डिपार्टमेंट की यह कौन सी नीति है कि इस माउन्टेनस एरिया को और ज्यादा अलंघ्य और दुर्गम न बना कर, इन में सड़कें बनायी जा रही हैं ताकि अगर कोई लड़ाई हो और हमारी फौजें दुर्भाग्य से पीछे हटें तो इन सड़कों का इस्तेमाल दुश्मन भी कर सके ? तो इन एरियाज़ को और कठिन न बना कर या जितने कठिन हैं उतने कठिन न रहने दे कर इन को आसान बनाने की कौन सी नीति है जो हमारे दुश्मन के भी इस्तेमाल में आ सकती है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री स्वर्ण सिंह : अब इसका मैं क्या जवाब दूं ?.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : लाजवाब है।

श्री स्वर्ण सिंह : हां, यह लाजवाब है, उनका कहना ठीक है।

Really, Sir, if one is in depression, no one can boost the morale of such a person. It is an amazing suggestion : that by our improving our roads we provide facilities to the enemy, is something which I cannot accept, and I would appeal to the hon. Member not to think on those lines.

Grants to States

*1259. SHRI B. N. KUREEL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether some States could not draw the Central grants for various schemes as they were not able to arrange the matching grants within the State during the Third Plan period and the period thereafter upto the end of 1967-68 ; and

(b) If so, which are the States and what were the various schemes for which grants were not drawn ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) and (b). Allocation of assistance to States, in the form of loans and grants, are made by the Ministry of Finance at the beginning of each financial year and funds are released to the States in instalments. Final adjustments which determine the actual utilisation of grants are made on the basis of audited figures of expenditure supplied by the State Governments.

The audited figures for the Third Plan period as a whole and upto the end of 1967-68 are still awaited from the State Governments.

श्री बी० एन० कुरील : क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1967-68 के वित्तीय वर्ष में वहां पर जो महिलाओं के कल्याण की और हरिजनों के कल्याण की योजनाएं थीं उन को बन्द कर दिया और यह कहा कि हम को केन्द्र से ग्रान्ट नहीं मिली क्योंकि हम मैचिंग ग्रान्ट नहीं दे रहे हैं, तो क्या यह बात सही है ?

श्री बी० आर० भगत : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से सम्बन्धित है और इस की तफसील मैं नहीं दे सकता.....

श्री हुकम चन्द कछवाय : तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं ? आप ने क्यों स्वीकार कर लिया ?

श्री बी० आर० भगत : हमने यह कहा था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को यह ट्रांसफर हो जाए। उन्होंने मान भी लिया था लेकिन...(**व्यवधान**) ...मैं अध्यक्ष महोदय से कहूंगा कि यह सवाल ट्रांसफर हो जाए तो पूरी तफसील में सूचना दी जायेगी।

श्री बी० एन० कुरील : अध्यक्ष महोदय, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए ही सवाल किया था। मेरी समझ में नहीं आया कि इन के पास कैसे गया ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जो उन्होंने कहा कि जो वहां स्कीमें रुक गई हैं वह सच है।

श्री बी० एन० कुरील : क्या केन्द्र सरकार की जानकारी में यह भी बात है कि ऐसी ही

बहुत सी स्कीमों को जैसे वृद्ध लोगों को पेंशन देने की स्कीम थी और रूरल हाउसिंग स्कीम थी वह भी इसी आधार पर वहां बन्द कर दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : इस के लिये सूचना मिले तो मैं जवाब दे सकता हूँ ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूँ क्या प्रधान मन्त्री का ध्यान उन समाचार पत्रों की ओर गया है जिन में यह कहा गया है गैर-कांग्रेसी सरकार जहां पर स्थापित है वहां पर उन्होंने इस बात की आलोचना की है कि केन्द्र हमें ठीक प्रकार से काम करने में सहयोग नहीं दे रहा है और उसके कारण से हमें सरकार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या इस प्रकार के समाचारों की ओर आप का ध्यान गया है ? यदि हां तो किन-किन राज्यों ने यह कहा है ? यह शिकायत किन-किन राज्यों की है ?

श्री ब० रा० भगत : जहां तक केन्द्रीय सहायता का सवाल है, सभी सरकारें—चाहे कांग्रेसी सरकारें हों या गैर-कांग्रेसी सरकारें हों—सब को यह शिकायत रहती है । हर राज्य सरकार यह समझती है कि उसे सहायता कम मिली है, मगर सहायता देने का तरीका और परिमाण कितना हो इस के लिये प्लानिंग कमीशन द्वारा गाइड-लाइन्ज बना कर तथा नैशनल डवेलपमेंट कान्सिल के परामर्श से इस को तय किया जाता है । इस लिये यह कहना कि गैर-कांग्रेसी सरकारों को शिकायत है कि केन्द्रीय सहायता ठीक से नहीं मिलती है—बिलकुल गलत है ।

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI : How is it that UP with 17 per cent population to its credit and a very backward economy to its discredit and with the unique distinction of having all the Prime Ministers from that State, only gets about 5 to 6 per cent of the money given in the form of grants or aid ? Is it because the various Governments in UP have not been able to demand more money in the form of aid and grants for the various schemes or is it because they have not succeeded in pressing the Centre to give more money for the various schemes ?

SHRI B. R. BHAGAT : As I said, guidelines have been evolved and as a result of that, 70 per cent of the assistance is given on the basis of population and the balance of 30 per cent is given on various other considerations. This is uniform for all the States. No State is discriminated against.

SHRI UMANATH : There is a stipulation that the amount must be spent only for that particular project for which it is earmarked and if the State Governments are not able to get the matching grants, the whole thing falls through. May I know whether the Government is prepared to give up this stipulation that that particular amount must be spent only for those projects and allow the State Governments to treat it as a general grant so that they can use it for other projects if it is not possible to use it for that particular project ?

SHRI B. R. BHAGAT : In the case of certain centrally-aided projects, this stipulation is there, because it is not a cent per cent grant from the centre. Part of it is given from here and a part of it is provided by the States. So, the States have to provide the matching grants. Such projects are naturally affected if the States are not able to provide the matching grants.

श्री क० ना० तिवारी : मैचिंग ग्रान्ट्स का जो स्टेट्स का हिस्सा था, उस को कितनी स्टेट्स ने नहीं दिया इस प्रश्न का जवाब देते हुए मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरे पास इस की फिगर्स नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि कब तक ये फिगर्स आजायेंगी और उन के आने के बाद क्या उन को सभा पटल पर रखा जायगा ?

श्री ब० रा० भगत : फिगर्स जब आ जावेंगी, तो जरूर रखी जावेंगी ।

श्री शिवचन्द्र झा : मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्टेट्स को सहायता देने के लिये सरकार ने कौन सा क्राइटेरिया (मापदण्ड) बनाया है—पौपुलेशन के आधार पर या नीड्स के आधार पर ? उस दृष्टि से बिहार में न्यूक्लियर पोटेन्शियेलिटीज का-मैटीरियल्ज की डवेलपमेंट के लिये तीनों प्लानों में अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

श्री ब० रा० भगत : इस के सम्बन्ध में एक दूसरा सवाल सं० 1267 है, जिस के उत्तर में हम एक स्टेटमेंट रख रहे हैं जिस में बताया गया है कि किस आधार पर हम सहायता देते हैं—सहायता के विवरण उस में दिया गया है ।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : What are the guidelines fixed by the Planning Commission on the basis of which the Central Government allots funds ? In some States, they are given more funds for extension of electricity and providing drinking water in villages. In Andhra, they are not able to extend electricity for want of funds. They have taken up a number of drinking water wells, but they are not able to complete them for lack of funds. At least for providing drinking water in the villages, will the Government consider providing some funds.

SHRI B. R. BHAGAT : The guidelines are : Every State should receive first a quantum of 70 per cent of the total amount to be distributed in proportion to population. The balance of 30 per cent is to be distributed after taking into account (i) the special needs of Jammu and Kashmir, Assam and Nagaland ; (ii) the requirements of continuing irrigation and power projects and (iii) the need for accelerated development of certain backward areas.

MR. SPEAKER : Next question No. 1260. Questions Nos. 1262 and 1269 also deal with the same subject of Kachchativu island. All these can be taken together. Mr. Patodia is absent, but it does not matter. Mr. Hem Barua is here.

Annual Festival in Kachchativu Island

*1260. SHRI SWELL : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the annual festival in the Kachchativu Island was celebrated this year ;

(b) the number of pilgrims from India who visited the Island ; and

(c) whether any Indian Official accompanied the pilgrims to look after the law and order and to generally ensure that the festival passed off peacefully ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Yes, Sir.

(b) Over 2,000 Indian pilgrims are reported to have visited the island.

(c) As in previous years, no Indian official accompanied the pilgrims to the Island.

Clearance for Pilgrims to Kachchativu Island

*1262. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Ceylon sent plain-clothed Policemen to Kachchativu Island for the duration of the Catholic Festival held there recently;

(b) whether it is also a fact that the pilgrims were asked to obtain clearance cards from these Policemen before entering the Island ; and

(c) if so, the reaction of Governmeni thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI B. R. BHAGAT) : (a) Government have seen some press reports to this effect.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Indian Pilgrims Prevented from Going to Kachchativu Island

*1269. SHRI HEM BARUA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that about 2,000 Indian pilgrims were prevented by the Indian Government from going to the Kachchativu Island on pilgrimage at the recent festival held there ; and

(b) if so, the reasons therefor ?